I urge upon the Government to assure this House that the factors responsible for the fire are made public and immediate steps are taken to ensure proper preservation of the films in future. I would like an assurance from the Minister in this regard. As a student of the Film and Television Institute of Pune, I have benefited from the invaluable films we have at NFAI and cannot adequately express how deeply pained cinestars like me are by this fire.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): मैडम, इस स्पेशल मैंशन के साथ अपने को सम्बद्ध करती हूं।

DR. C. NARAYANA REDDY (Nominated): Madam, I also associate myself with this Special Mention.

उपसभापति: डा॰ कुमकुम राय। वैसे कल श्री सुरेश पचौरी जी ने इसे उठाया था और इस विषय में कोई स्टेटमेंट भी हैल्थ मिनिस्टर ने लोक सभा में दी है। मुझे लगता है कि यहां भी कुछ होना चाहिए।

Hazard posed to human health by contaminated bottled drinking water

डॉ॰ कुमकुम राय (बिहार): धन्यवाद। मैडम, स्टेटमेंट तो होती रहती है लेकिन हमारे देश में नदियों के जल पर और बोतल में बंद पानी पर भी विवाद है। इसलिए इस पर स्पेशल मेंशन और स्पेशल कार्रवाई की जरूरत है। मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से कुछ कहना चाहती हूं।

पिछले एक-डेढ़ दशक में बोतलबंद मिनरल वाटर के बढ़ते व्यापार एवं उपभोक्ताओं द्वारा उसे सुरक्षित समझकर उपयोग करने की प्रवृत्ति ने समाज को हैरत में डाला था किंतु पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठन सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली में 17 और मुंबई में 3 मिनरल वाटर ब्रांडों के नमूनों के परीक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं उन्हें जानकर आशंकाओं एवं चिंता का जनमानस में व्याप्त होना स्वाभाविक है। इन तथाकथित सुरक्षित समझे जाने वाले जल में 5 अलग-अलग हानिकारक कीटनाशक के तत्व पाए गए। जांचानुसार दिल्ली में मिनरल जल के ब्रांडों में कीटनाशकों की मात्रा पेय जल मानक स्तर से 36.4 गुणा ज्यादा पाई गई जबकि मुंबई में 16.7 गुणा अधिक पाई गई। लिंडेन, डी.डी.टी., माल्थयोन और क्लोपाइरिफोस जैसे खतरनाक कीटनाशकों का भूमिगत जल स्रोत्रों या बोतलबंद जल में होने से कैंसर, स्तन कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप, कब्ज और गुर्दे की बीमारियां होती हैं। इसका सबसे बुरा असर मासूम बच्चों पर पड़ता है। कृषि प्रधान राज्यों में किसानों द्वारा अधिक फसल प्राप्त करने के उद्देश्य से कीटनाशकों रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी जल प्रदूषण बढ़ा रहा है। भूमिगत जल स्रोत निरन्तर नीचे गिरते चले जा रहे हैं। फलत: जल में लवणता बढ़ती चली जा रही है। शोधकर्त्ताओं का कहना है कि

दिल्ली जल बोर्ड का पानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सीलबंद मिनरल वाटर की तुलना में पांच गुना अधिक घातक है। आखिर जनता किसे शुद्ध जल मानकर इस्तेमाल करे? समस्त जल स्रोतों के प्रदूषित होने से भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार ध्यान दे एवं जल नीति ऐसी बनाई जाए ताकि जनता को कम से कम शुद्ध पेय जल मुहैया हो सके। धन्यवाद।

डा॰ अबरार अहमद (राजस्थान): मैडम, मैं स्वयं को इससे एसोसिएट करता हूं। सरकार ने विरोधाभास की स्थिति पैदा कर दी है। एक मंत्रालय आई.एस.आई. मार्क वापस ले रहा है और कल मंत्री जी ने उस हाउस में बयान दिया, जिसे हमने टी.वी. पर देखा, वे कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल ठीक है। सारे देश को कन्फ्यूजन की स्थिति में सरकार डाल रही है। यह स्पष्ट करना चाहिए कि बोतलबंद पानी खराब है या अच्छा है। माननीय मंत्री जी का उस सदन में कल का बयान, जिसमें उन्होंने चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि पानी बिल्कुल ठीक है और दूसरी तरफ एक मंत्रालय आई. एस.आई. मार्क वापस ले रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? इस विरोधाभास को दूर किया जाना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): मैडम, हम लोगों के मन में आशंका होती है कि इसमें भी घोटाला हो रहा है।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): सरकार इस पर स्टेटमेंट देगी या नहीं, यह मंत्री जी बता दें ....(**व्यवधान**)...

डा॰ अबरार अहमद: यही चीज बोतल में बेचते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: यह एजिटेशन हो रहा है ...(**व्यवधान**)...सेशन चल रहा है ...(**व्यवधान**)....मैडम, पूछ दीजिए कि क्या यह सरकार स्टेटमेंट देगी ...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): मैडम, बी.आई.एस. पर डिसकशन कराइए ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: डिसकशन छोड़िए, पहले प्वाइंट यह है कि आप सरकार से पूछ लीजिए कि वह स्टेटमेंट देगी या नहीं ...(**व्यवधान**)...

डा॰ कुमकुम राय: इतने दिनों से बवेला मचा हुआ है ...(**व्यवधान**)...एक दिन में कैसे ठीक होगा ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...

डा॰ अबरार अहमद: एक तरफ कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल ठीक है, अच्छा है और दूसरा मंत्रालय आई.एस.आई. मार्क वापस ले रहा है ...(**व्यवधान**)...बहुत कन्फ्यूजन है ...(**व्यवधान**)...सरकार को विरोधाभास दूर करना चाहिए।

श्री नीलोत्पल बसु: सरकार स्टेटमेंट देगी या नहीं यह पूछ लीजिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday, I saw two contradictory statements on the television. The Minister of Health said on the floor of the Lok Sabha that they have tested the water and the water was clean. While the Minister of Consumer Affairs said that he was withdrawing the ISI mark. Now, there is some confusion in everybody's mind, including mine, because I did not know that is right. So, will you please ask the Government and the concerned Minister to come out and enlighten us as to what is the truth?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): उपसभापति जी, वैसे तो कल जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने लोक सभा के अंदर बयान दिया है उसमें उनका यही कहना था कि जो मापदंड हमने बनाए थे उन पर तो यह पानी अभी खरा उतरता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर जो नए-नए और अच्छे मापदंड आए हैं, उनके हिसाब से उसमें कुछ पाया गया है कि शायद कुछ कमी हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो मापदंड हैं उन पर तो यह पानी खरा उतरा है। इसलिए घबराहट की उसमें कोई जरूरत नहीं है। किन्तु फिर भी उपसभापति जी ने मेरे ध्यान में यह लाया है कि जिसके कारण जो दूसरा मंत्रालय है, उसने आई॰एस॰आई॰ मॉर्क विदड्रॉ किया है, तो मैं चाहूंगा कि संबंधित मंत्री इस सदन के अंदर कोई बयान दें।

डॉ॰ अबरार अहमद: दोनों मंत्री बयान दें।

Need for rehabilitation of tribals in the country

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): More than eight crore tribal population in our country today are economically deprived and socially oppressed section. They constitute a major portion of landless rural poor and contract labour in mines, plantation, etc. Due to curtailment of P.D.S., cut in the social sector funds, large-scale privatisation, attack on public sector, repression perpetrated on them by the mafias, contractors, etc., the lives of this section of rural poor are most deplorable. They are today faced with the threat of losing their language and culture also. Forest is their natural habitat. The relationship between tribals and the conservation of forest is an integral part of their existence. Any eviction of the tribals without solving their problem would be detrimental to their interest. The Government should, therefore, think over the problem very seriously.